

पोषण सुरक्षा: एक त्रिआयामी दृष्टिकोण

यह अडिटोरियम 20/10/2023 को 'हंडि बजिनेस लाइन' में प्रकाशित "An opportunity to recast India's food system" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की खाद्य प्रणाली के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं अवसरों के बारे में चरचा की गई है और उपभोक्ताओं, उत्पादकों एवं मध्यस्थों को संलग्न करते करते हुए एक त्रियी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें स्वस्थ एवं सतत आहार को बढ़ावा देने, कृषिआय की वृद्धिकरने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लक्ष्य पर भी विचार किया गया है।

प्रलिमिस के लिये:

विश्व बैंक, मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा, आरथिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंघ (ICESCR), कृपोषण, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याहन भोजन, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मशिन, कसिन उत्पादक संगठन (FPO)

मेन्स के लिये:

खाद्य सुरक्षा: महत्व, स्थिति, चुनौतियाँ और आगे की राह

16 अक्टूबर को 'विश्व खाद्य दिवस' (World Food Day) मनाया गया, लेकिन हम खाद्य को एक प्रणाली या तंत्र के रूप में कम ही देखते हैं। खाद्य प्रणाली की चुनौतियों को भारत से बेहतर कोई देश नहीं समझ सकता, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरना पड़ता है। जबकि खाद्य प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य सभी के लिये पोषण सुरक्षा (nutrition security) सुनिश्चित करना है, इसे सतत या संवहनीय रूप से तभी प्राप्त किया जा सकता है जब खाद्य उत्पादक ऐसे उपयुक्त आरथिक प्रतिलिपि प्राप्त करें जो समय के साथ प्रत्यास्थी (resilient) सदिध हो।

यह प्रत्यास्थता हमारे प्राकृतिक पारस्परियतिकी तंत्र की प्रत्यास्थता से जटिल रूप से जुड़ी हुई है क्योंकि कृषि के लिये सबसे बड़े आदान या इनपुट—जैसे मृदा, जल एवं जलवायु दशाएँ, प्राकृतिक संसाधन ही हैं। आजीविका और प्रयावरण सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा के इस अंतरसंबंध को महत्व देना हमारी खाद्य प्रणाली को वास्तव में संवहनीय बनाने के लिये आवश्यक है।

पोषण सुरक्षा का क्या महत्व है?

- **स्वास्थ्य और पोषण:** पोषण सुरक्षा कुपोषण और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं—जैसे स्टंटगी, संज्ञानात्मक अपंगता एवं रोग संवेदनशीलता को रोककर व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सेहत में सुधार करती है।
 - 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग 45% मौतें कुपोषण से संबद्ध होती हैं।
- **आरथिक स्थिरता:** पोषण सुरक्षा व्यक्तियों और राष्ट्रों को अधिक उत्पादक बनाने, आय उत्पन्न करने और व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाकर उनकी आरथिक स्थिरता की वृद्धिकरती है।
 - विश्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि उत्पादकता की हानि और मानव पूंजी के संदर्भ में कुपोषण क्षेत्र के लिये वर्ष 3.5 दरलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी:** पोषण संबंधी सुरक्षा मधुमेह और हृदय रोग जैसी आहार-संबंधी बीमारियों को रोककर स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम कर सकती है। इससे फिर स्वास्थ्य देखभाल पर एक बड़ा बोझ कम होता है।
 - कुल स्वास्थ्य व्यय (Total Health Expenditure- THE) में जेबी खर्च (Out-of-Pocket Expenditure- OOPE) की हस्तियों द्वारा लगभग 47% है।
- **निधनता उन्मूलन:** यह सुनिश्चित करना कि लोगों को पौष्टिक भोजन मिले, निधनता उन्मूलन का एक साधन है। पोषण संबंधी सुरक्षा का अभाव निधनता चक्र (cycle of poverty) को बनाये रख सकता है, क्योंकि कुपोषण शैक्षिक प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है और आय-अर्जन कषमता को कम कर सकता है।
- **सतत कृषि और प्रयावरण संरक्षण:** पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने में प्रयावरण को संरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ियों भी अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करना:** पोषण सुरक्षा जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिती है; यह परदृश्य तब उत्पन्न होता है जब किसी देश की आबादी का एक बड़ा भाग कार्यशील आयु वर्ग में होता है। सुपोषण व्यक्तियों के उत्पादक होने और आरथिक विकास में योगदान करने की अधिक संभावना होती है, इसलिये जनसांख्यिकीय लाभ का पूर्ण दोहन किया जाना चाहिये।

- **झटकों के प्रतिप्रत्यास्थता:** पोषण संबंधी सुरक्षा समुदायों और व्यक्तियों को आरथकि, प्रयावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी झटकों के प्रतिअधिक प्रत्यास्थी बनने में मदद करती है। विधि और पोषणकि आहार ग्रहण करने वाले लोगों को प्राकृतिक आपदाओं या स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे वभिन्न संकटों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद मलि सकती है।
 - **कोवडि-19** महामारी ने खाद्य प्रणालयों की भंगुरता/संवेदनशीलता और कुपोषण एवं भुखमरी के प्रतिवृहत आबादी की भेद्यता को उजागर कर दिया है। इसलिए, स्वस्थ भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करना और आहार विधिता को बढ़ावा देना ऐसी महामारियों एवं इनके प्रभावों के विरुद्ध प्रत्यास्थता के निर्माण के लिये आवश्यक है।
- **मानव गरमि और समता:** पोषण सुरक्षा खाद्य को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में चहिनति कर मानवीय गरमि और समता का सम्मान करती है जो सभी लोगों के लिये उनकी सामाजिक-आरथकि स्थितिया भौगोलिक स्थितिपर वचिर कथि बनि सुलभ होना चाहयि।
 - **खाद्य या भोजन का अधिकार (right to food)** एक कानूनी अधिकार है जसि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration on Human Rights) और आरथकि सामाजिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंवदि (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR) में भी मान्यता प्राप्त है।

भारत में पोषण सुरक्षा की स्थिति

- पोषण के मोरचे पर भारत कुपोषण के दोहरे बोझ (double burden of malnutrition) का सामना कर रहा है।
 - एक ओर, पछिले कुछ वर्षों में वयापक प्रगति के बावजूद भारतीय आबादी के एक बड़े भाग में पोषक तत्वों की कमी प्रदरशति होती है।
 - **राष्ट्रीय प्रविवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21** के अनुसार 35% बच्चे **सुरक्षित** के शकिर हैं, जबकि 57% महलिएँ और 25% पुरुष एनीमिया से पीड़िति हैं।
 - दूसरी ओर, असंतुलित आहार और गतहीन जीवन शैली के कारण 24% वयस्क महलिएँ और 23% वयस्क पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं।

पोषण सुरक्षा के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **कृषि की नमिन उत्पादकता:**
 - उत्पादन के मामले में, सीमांत और छोटे कसिनों की आवश्यकताओं की पूरताके लिये कृषि आय अप्राप्त है।
 - 'ट्रांसफर्मर्सि रूरल इंडिया फाउंडेशन' की एक रपिएट के अनुसार, 68% से अधिक सीमांत कसिन अपनी आय को गैर-कृषि गतिविधियों से पूरकता प्रदान करते हैं।
 - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय गरमानी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/ MGNREGA)** के तहत प्रदत्त शर्म और अन्य प्रकार के अस्थायी शर्म में कमी आ रही है जो आय विधिकरण के लिये कौशल या अवसरों की कमी का संकेत देता है।
- **घटते प्राकृतिक संसाधन:**
 - घटते प्राकृतिक संसाधन और बदलती जलवायु भारत के खाद्य उत्पादन को अत्यधिक असुरक्षित बना रही है।
 - वर्ष 2023 के मृदा स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में कृषियोग्य भूमि के लगभग आधे भाग में जैवकि कारबन—जो मृदा स्वास्थ्य का एक आवश्यक संकेतक होता है, की कमी हो गई है।
 - भूजल—जो सचिरी का सबसे बड़ा स्रोत है, तेज़ी से घटता जा रहा है।
 - पंजाब जैसे राज्यों में 75% से अधिक भूजल आकलन स्थानों (groundwater assessment locations) का अत्यधिक दोहन कथि गया है, जसिसे कृषि आय की प्रत्यास्थता को खतरा पहुँच रहा है।
- **दोषपूरण खाद्य वितरण प्रणाली:**
 - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से अप्राप्त खाद्य वितरण बढ़ती खाद्य असुरक्षा में योगदान देता है। **लक्षण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted PDS- TPDS)** दोषपूरण मानदंडों के कारण पात्र उम्मीदवारों को अपवर्जित कर देता है, जसिसे APL या BPL के रूप में दोषपूरण वर्गीकरण की स्थितिबनती है। इसके परणिमस्वरूप खाद्यानन्द उठाव में कमी आती है और नमिन गुणवत्तायुक्त अनाज एवं PDS दुकान की बदलत सेवा के कारण स्थितिबद्तर बन जाती है।
- **पोषण कार्यक्रमों की निगरानी का अभाव :**
 - देश में कई योजनाएँ लाई गई हैं जो पोषण में सुधार लाने का लक्ष्य रखती हैं, लेकन इन्हें ठीक से करयानवति नहीं कथि गया है।
 - उदाहरण के लिये, कई राज्य मध्याहन भोजन योजना (MDMS) को प्रभावी ढंग से लागू करने में वफिल रहे हैं।
- **अंतर-क्षेत्रीय समनवय का अभाव :**
 - सुसंगत खाद्य एवं पोषण नीतियों की कमी के साथ-साथ सरकार के वभिन्न मंत्रालयों—जैसे महलि एवं बाल स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं प्रविवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि के बीच अंतर-क्षेत्रीय समनवय की कमी ने समस्या को बढ़ा दिया है।

पोषण सुरक्षा को संबोधित करने हेतु क्या दृष्टकिणे अपनाया जा सकता है?

- **उपभोक्ता संलग्नता और मांग में बदलाव:**
 - उपभोक्ता मांग को सवस्थ एवं सतत आहार की ओर स्थानांतरति करने की आवश्यकता है। हमें ऐसेखाद्य वकिलपूँ को अपनाने की ज़रूरत है जो लोगों के लिये और हमारे ग्रह के लिये स्वास्थ्यवरदधक हो।
 - हम निर्माण द्वारा उपयोग कथि जा रहे दृष्टकिणे का पालन करते हुए आयातति की जाती जई/ओट्स या क्वनिओआ की तरह ही भारत में स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले **मोटे अनाजों (millets)** को लोकप्रयि बना सकते हैं।
 - नागरकि समाज और स्वास्थ्य समुदाय सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स के साथ साझेदारी का निर्माण कर लाखों लोगों के लिये स्वस्थ एवं संवहनीय उपभोग को आकार दे सकते हैं।

- सार्वजनिक क्षेत्र PDS, मध्याहन भोजन, रेलवे खानपान, अरबन कैटीन और सार्वजनिक एवं संस्थागत खरीद के माध्यम से कम से कम 70% भारतीयों के उपभोग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
- धार्मिक संस्थाएँ भी खाद्य विकल्पों को प्रभावित करने के रूप में योगदान दे सकती हैं, जैसा कतिरिमाला तरिपत्ति देवस्थानम् द्वारा किया जा रहा है।
 - तरिमाला तरिपत्ति देवस्थानम्—जो प्रत्येक लाभग 70,000 लोगों को सेवा प्रदान करता है, अब प्राकृतिक रूप से उगाये गए उत्पादों की खरीद कर रहा है।
- कृषक और सतत कृषि का समरथन:
 - हमें कसिनों को लाभकारी एवं पुनर्योजी कृषि अभ्यासों की ओर आगे बढ़ने का समरथन करना चाहिये ताकि उनके लिये प्रत्यास्थी आय सुनिश्चित हो सके।
 - **प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Natural Farming)** इस दशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन सतत कृषि के लिये कुल वित्तपोषण कृषिबिजट के 1% से भी कम है।
 - हमें वभिन्न कृषि-पारस्थितिकी अभ्यासों—जैसे कृषि विनियोगी, संरक्षण कृषि, परशिद्ध खेती आदि के लिये ऐसी पहलों को व्यापक और वसितारति करने की आवश्यकता है।
 - कृषि सहायता को इनपुट सबसड़ी से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक खेती के लिये कसिनों को प्रत्यक्ष नकद सहायता देने की ओर केंद्रति होना चाहिये।
 - यह इनपुट के कुशल उपयोग को बढ़ावा देगा, साथ ही कृषि-पारस्थितिकी अभ्यासों के फलने-फूलने के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।
 - कृषि अनुसंधान और वसितार सेवाओं को अपने बजट का एक हस्तिसा सतत कृषि अभ्यासों पर ध्यान केंद्रति करने के लिये आवंटति करना चाहिये, जो कसिनों को सतत कृषि के लिये आवश्यक ज्ञान एवं उपकरण प्रदान कर सकता है।
- संवहनीय 'फार्म-टू-फोर्क' मूल्य शृंखला का निर्माण करना:
 - गरामीण आय बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिये किसिनों को सृजति मूल्य का उच्चति हस्तिसा प्राप्त हो, अधिक संवहनीय एवं समावेशी मूल्य शृंखला का निर्माण करना महत्वपूर्ण है।
 - मध्यस्थी और नगिमों को कसिनों से प्रत्यक्ष खरीद के लिये प्रोत्साहित करना—वशीष रूप से उन कसिनों से जो संवहनीय एवं नैतिक अभ्यासों का पालन करते हैं, महत्वपूर्ण है।
 - 'रेस्पॉन्सिबिल सोर्सिंग' (responsible sourcing) को बढ़ावा देने के लिये निषिक्ष व्यापार सदिधांतों जैसे प्रोत्साहनों को लागू किया जा सकता है।
 - 'DeHaat' और 'Ninjacart' जैसे वभिन्न नए एग्री-टेक उद्यम ऐसे 'फार्म-टू-बायर लिंकेज' को सक्षम कर रहे हैं।
 - **कसिन उत्पादक संगठनों (FPOs)** को अन्य FPOs के साथ अपनी उपज का व्यापार करने की अनुमति दिने से कसिनों को अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि FPOs में शामलि कसिन परवार भी कृषि उत्पाद की खरीद करते हैं।
 - ओडिशा में कुछ FPOs पहले ही इस दृष्टिकोण से कारब्य कर रहे हैं।
 - ओडिशा ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन (OOFA) जैविक उत्पादों के उत्पादन से संलग्न FPOs का एक संघ है। OOFA ओडिशा में अन्य FPOs के साथ-साथ भारत के अन्य राज्यों के FPOs के साथ जैविक उत्पादों का व्यापार करता है। इससे OOFA को अपने सदस्यों के उत्पादों के लिये बेहतर मूल्य पाने और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने में मदद मिली है।

निषिकरण

संपूर्ण खाद्य प्रणाली को स्थानांतरित करना कोई छोटी उपलब्धिनहीं है। लेकिन चुनौती के पैमाने से हमारी महत्वाकांक्षाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिये। यद्यपि तेज़ी से कारब्य करें तो भारत के पास शेष वशिष्व को यह दिखाने का एक अनूठा अवसर मौजूद है कि अपनी खाद्य प्रणाली को कैसे दुरुस्त किया जाए।

अभ्यास प्रश्न: भारत में पोषण सुरक्षा की स्थितिपर विचार कीजिये, इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिये और इन चुनौतियों से निपटने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????

Q.1 जलवायु-स्मार्ट कृषि के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में नमिनलिखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- भारत में 'जलवायु-स्मार्ट गाँव' दृष्टिकोण जलवायु परवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा (CCAFS), एक अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम के नेतृत्व में एक परियोजना का एक हस्तिसा है।
- CCAFS की परियोजना फ्राईस स्थितिअंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान (CGIAR) के सलाहकार समूह के तहत की जाती है।
- भारत में अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिये अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) CCAFS के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3

- (c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

Q.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कथि गए प्रावधानों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजिये: (2018)

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL)' की शरेणी में आने वाले परविार ही सबसडी वाले खाद्यानन प्राप्त करने के पातर हैं।
2. राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महलिया, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, घर की मुख्यिया होगी।
3. गर्भवती महलियाँ और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद छह महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी का 'टेक-होम राशन' मिलता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????

Q.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के साथ मूल्य सबसडी के स्थान पर भारत में सबसडी का परदृश्य कसि प्रकार बदल सकता है? चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/26-10-2023/print>